

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3490

जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

एचपीसीएल का कार्यनिष्पादन

3490. श्री राधेश्याम बिश्वास:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कछार पेपर मिल्स (सीपीएम) सहित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की विभिन्न कागज-इकाइयों के कार्य-निष्पादन का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सीपीएम सहित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की कुछ इकाइयां पिछले कुछ वर्षों से निरंतर घाटे में चल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का सीपीएम सहित इन कागज-इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की दोनों इकाइयों अर्थात नगांव पेपर मिल (एनपीएम) और कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम) का निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	एनपीएम	सीपीएम	एचपीसी
उत्पाद (एमटी)			
2012-13	86280	52683	138963
2013-14	80022	64037	144059
2014-15 (जून माह तक)	24241	22465	46706
बिक्री (एमटी)			
2012-13	83609	54403	138012
2013-14	78589	61769	140358
2014-15 (जून माह तक)	20012	17626	37638
पीएटी (₹ करोड़ में)			
2012-13			(-)151.87
2013-14			(-)115.00
2014-15 (जून माह तक)			3.12

(ख): हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) की इकाई कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम), 2009-10 से लगातार हानि में चल रही है। इसकी स्थापना अवसंरचनात्मक कमी वाले और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में हुई थी जहां कार्य संचालन संबंधी सभी अड़चनें थीं। कुछ वर्ष पहले तक एचपीसी लाभ अर्जित करने वाली और लाभांश अदा करने वाली कंपनी थी। शुरुआत में, बांस के सामूहिक पुष्पन की वजह से बांस की अनुपलब्धता के कारण 2008-09 से सीपीएम के क्षमता उपयोग में कमी होने लगी। बाद में यह स्थिति मिजोरम सरकार द्वारा

28.03.2011 से परिवहन पर तथा मिजोरम राज्य, जहां से सीपीएम की बांस की कुल आवश्यकता की 60% पूर्ति हुआ करती थी, वहां से बांस आपूर्ति पर व्यापार प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से और अधिक खराब हो गई। मूलभूत कच्चा माल अर्थात् बांस की अनुपलब्धता के कारण सीपीएम अपनी क्षमता का लगभग केवल 52% ही उपयोग कर सका। सीपीएम में घटते-बढ़ते क्षमता उपयोग तथा इसके अलावा अत्यधिक नियत लागत से लागत में और वृद्धि हो गई, जिसके कारण एचपीसी को हानि हुई। सीपीएम में इष्टतम क्षमता उपयोग न होने से न सिर्फ इस इकाई बल्कि समग्र रूप से कंपनी के परिचालन और वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई।

तथापि, मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर किए गए उपायों से मिजोरम राज्य से जनवरी, 2014 के अंत से बांस की आपूर्ति अंततः पुनः आरंभ होने में सहायता मिली और तब से क्षमता उपयोग में सुधार होना शुरू हुआ है, जो अब 90-92% के बीच है। सभी प्रतिकूलताओं का सामना करने के बावजूद, सीपीएम अब 100% क्षमता उपयोग के लिए तैयार हो रहा है, परन्तु कोयले की उपलब्धता एक नया मुद्दा है जिसने कंपनी को दोबारा गहरे संकट में धकेल दिया है। सीपीएम को मेघालय राज्य से कोयले की प्रचुर उपलब्धता के आधार पर स्थापित किया गया था, जिस पर यह 100% निर्भर है और जहां से कोयला खनन तथा परिवहन पिछले 75 दिनों से बंद हो जाने की वजह से आपूर्ति रुक गई है। जब तक मेघालय राज्य से कोयले की आपूर्ति बहाल नहीं होती है, तब तक सीपीएम में काम चालू रहने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सड़क की हालत खराब होने तथा कोयले की ढुलाई लमडिंग से किए जाने पर रेलवे द्वारा रोक लगाए जाने की वजह से कहीं और से कोयला लाए जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है।

(ग): सीपीएम में परिचालन चालू रखने के कई सारे उपाय भारत सरकार ने पहले ही किए हैं।

(घ): लागू नहीं।
